Industries is also implementing various Plan Schemes under which financial assistance is provided to State Governments/Joint Sector/ Cooperative Sector etc.

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजना**

3838. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सहित सभी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास कम होने के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं बनाई गई है;

(ख) क्या इस स्थिति के परिणामस्वरूप निजी निवेशकों द्वारा निवेश नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में वर्ष 1996-97 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय):** (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश भर में इसमें त्रिपुरा शामिल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें बनाई और लागू की हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान भी ऐसी स्कीमों को लागू करने का प्रस्ताव है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष।

जुलाई, 1991 से अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों और अनुमोदनों के मार्फ़्त लगभग 7700 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश समेत मुख्यत: निजी क्षेत्र द्वारा 63200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं में से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश की परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा चुका है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण के विकास के लिए केन्द्र / राज्य सरकार के संगठनों, संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त परियोजनाओं, स्वयंसेवी एजेंसियों, सहकारिताओं, निजी उद्यमियों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1996-97 के दौरान हमारी स्कीमों के लिए परिव्यय 40 करोड़ रुपये था।

**मध्य प्रदेश में आम प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता दिया जाना**

3839. **श्री अजीत जोगी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में आम प्रसंस्करण उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाएं स्वीकृति हेतु सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय):** (क) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मध्य प्रदेश समेत देश में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों, इसमें आम प्रसंस्करण उद्योग शामिल है, की स्थापना/विस्तार/उन्हें बेहतर बनाने के वास्ते सहायता उपलब्ध कराने हेतु फल तथा सब्जी, प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनेक विकास योजना स्कीमें चला रहा है। ये स्कीमें राज्य विशेष नहीं होतीं। वैसे मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाना**

3840. **श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है और उसे लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार में ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने में आयोग की अब तक क्या भूमिका रही है?

**उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन):** (क) से (ग) बिहार राज्य सहित पूरे देशभर में यथासंभव अधिकाधिक जीव्यक्षम खादी तथा ग्रामोद्योग एककों को बढ़ावा देने की खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की कोशिश रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 2002 ई॰ सन् के अन्त तक के वी आई क्षेत्र में 5.6 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार सृजित करने के लिए खादी तथा

ग्रामोद्योग अयोग, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, संस्थान तथा संस्थानों के संघ के साथ संयुक्त रूप से कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी सुधार, औद्योगिक संपदा की स्थापना इत्यादि के रूप में सहायता सेवाओं का जाल फैला रही है। अपने सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 125 ब्लॉक विकास कार्यक्रम, जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन, हस्तनिर्मित कागज तथा चमड़ा जैसे विशेष कार्यक्रम भी चलाये हैं। बिहार में के वी आई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 125 ब्लॉक कार्यक्रम के अधीन 11 ब्लॉकों को चुना गया है तथा जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम के अधीन 4 जिलों को चुना गया है।

**Annual growth in the industrial sector**

3841. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are committed to maintain a 12% annual growth in the industrial sector;

(b) the growth rate of industrial production during the Sixth, Seventh and Eighth Five Year Plan;

(c) in what manner Government propose to achieve the 12% growth rate; and

(d) the details of measures taken in this regard so far?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The Common Minimum Programme of the Government has envisaged maintaining industrial growth at 12%. The growth rate of industrial production during Sixth, Seventh and Eighth Five Year Plan stood at 5.9%, 8.5% and 7.3% (expected).

(c) and (d) Sector specific strategies have already been initiated to remove constraints in under performing sectors. The credit policy announced recently by Reserve Bank of India is also expected to provide further impetus to industrial growth. Government has also proposed initiatives in the Union Budget 1997-98 for accelerated industrial growth. Domestic and foreign investment is encouraged in industry and infrastructure sectors.

**Privatisation of BHEL and SAIL**

3842. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal for privatisation of Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) and Steel Authority of India Limited (SAIL) under consideration;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the specific reasons for privatisation of these two Government companies?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

**उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त होना**

3843. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में उद्योग स्थापित करने के लिए विदेशों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस संबंध में संयुक्त उद्यमों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें राज्य-वार कितना-कितना निवेश किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या देश में इन उद्योगों की स्थापना से समग्रत: निकलने वाले परिणामों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है?

**उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन):** (क) से (ग) 1 अगस्त, 1991 से 31 दिसम्बर, 96 तक की अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निदेश के कुल 10119 (वित्तीय तकनीकी) प्रस्ताव अनुमोदित किये गए हैं जिनमें 95591.71 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है। इन विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों के राज्य वार ब्यौरे विवरण में दिये गए हैं। **(नीचे देखिए)**।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् विदेशी सहयोगी का नाम तथा देश, अन्तर्ग्रस्त इक्विटी निवेश, विनिर्माण की मद/कार्यकलाप भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूजलेटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं और इनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद की लाइब्रेरी को भेजी जाती हैं।

(घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है।